authorities in time. However the police authorities have been requested to expedite issue of reports in 8 weeks' time.

Number of Passports issued by Passport Office Lucknow in July, 1985 is 2820 as against 2132 in June, 1985.

Number of passports issued by Passport Office Bareilly in July, 1985 is 5530 as against 4340 in June, 1985.

आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए पुलिस बलों में सुधार किया जाना

2718. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 3 अगस्त को हैदराबाद में शिवरामपल्ली में बल्लभभाई पुलिस अकादमी में भाषण देते समय प्रधान मंत्री ने यह टिप्पणी की थी कि आतंकवाद के खतरे का मुकाबला करने के लिये पुलिस द्वारा अपनाये जा रहे परम्परागत तरीके पर्याप्त नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो पुलिस बलों को आधुनिक बनाने के लिये सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा): (क) जी हां,श्रीमान ।

(ख) यद्यपि संविधान के अधीन "पुलिस और विधि व्यवस्था" राज्य के विषय हैं, तथापि केन्द्र सरकार राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के अधीन राज्यों को उनके पुलिस बलों का आधुनिकीकरण करने के लिए धनराशि प्रदान कर रही है ।

विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार किये गये हैं और राज्य पुलिस बलों के लिए आयोजित किये जाते हैं ताकि उन्हें आतंकवाद रोकने की तकनीक में प्रशिक्षण दिया जा सके ।

लेथार्जी इन दि इंडियन एम्बैसीज एबराड

2719. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 अगस्त, 1985 के "ट्रिब्यून" में प्रकाशित "मिनिस्ट्री आफ एक्सटर्नल अफेयर्स कनसर्न्ड ओवर दि लेथार्जी आफ आवर एम्बैसीज" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार इस मामले मे क्या उपचारी उपाय करने का विचार रखती है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) चंडीगढ़ से प्रकाशित "संडे ट्रिब्यून" के 4 अगस्त, 1985 के इस अंक में इस प्रकार का कोई समाचार नहीं छपा है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) विदेशों में स्थित हमारे मिशनों के कार्य-संचालन के मुख्यालय द्वारा निरन्तर समीक्षा की जाती है । आवधिक रुप से निरीक्षण दल विभिन्न मिशनों का दौरा करते है ताकि उनके कार्य निष्पादन का "मौके पर" निरीक्षण और मूल्यांकन किया जा सके ।

Orders sanctioning the increase in freedom fighters' pension

2720. SHRI SYED AHMAD HASHMI: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government have passed the orders of the freedom fighters' pension

which was increased to Rs. 500 per month with effect from 1st July, 1985;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) whether it is also a fact that the Treasury Office at Tis Hazari, Delhi has not received the above orders with the result that the freedom fighters and their widows are not receiving the pension with the new rates and are facing a lot of difficulties; and

(d) if so, what action has been taken by Government to release the orders and make payment to the freedom fighters?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRIMATI RAM DULARI SINHA): (a) and (b) It has been decided to raise the amount of monthly pension admissible to the freedom fighters and widows of deceased freedom fighters under the Swatantrata Sainik Samman Pension Scheme to Rs. 500 p.m. with effect from 1-6-1985.

(c) and (d) Formal instructions for payment of pension at enhanced rates are expected to be issued soon.

लघु उद्योगों के लिए परीक्षण सुविधाओं का उपबंध

2721. **श्री प्यारेलाल खंडेलवाल :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योगों के अधीन स्थापित किए जाने वाले इलैक्ट्रानिकी उद्योगों के लिए परीक्षण सुविधाओं की व्यवस्था करने हेतु इन्दौर में इलैक्ट्रानिक परीक्षण और विकास केन्द्र की स्थापना करने के लिये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भेजा गया प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास लंबित पड़ा हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय लिया जा रहा है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और महासागर विकास, परमाणु, ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रानिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज पाटिल) : (क) जी, नहीं। इंदौर में इलेक्ट्रानिकी परीक्षण तथा विकास केन्द्र स्थापित करने की अनुमति दी जा चुकी है । इलेक्ट्रानिकी परीक्षण तथा विकास केन्द्र, इंदौर के संबंध में इलेक्ट्रानिकी विभाग मध्य प्रदेश सरकार के उद्योग विभाग के साथ और आगे बातचीत कर रहा है।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) को ध्यान में रखते हुये यह प्रश्न ही नहीं उठता।

Family beach at Goa

2722. PROF. C. LAKSHMANNA: Will the PRIME MINISTER be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 1256 given in the Rajya Sabha on the 28th March, 1985 and state:

(a) the progress made in the construction of a family beach in Goa;

(b) the total cost of the project; and

(c) by when the beach is likely to be opened to the public?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI ASHOK GEHLOT): (a) to (c) According to the information available with the ITDC, M/s. Sima Hotels and Resorts Ltd. are in the process of finalising the outlines of the project, its cost and the financial arrangements. Therefore, it is not possible at this stage to indicate the date by when the project would be completed.

Lion sanctuaries

2723. PROF. C. LAKSHMANNA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the number of lion sanctuaries in the country;

(b) the number of lions and other wild animals in these sanctuaries-sanctuary-wise and on the end of 1983 and 1984;

(c) what steps Government have taken to protect lions in these sanctuaries;